

12.41 hrs.

PETITION RE ENQUIRY INTO
AFFAIRS OF CONTAINERS AND
CLOSURES LIMITED AND ITS
NATIONALISATION

SHRI SAUGATA ROY (Barrack-
pore) I beg to present a petition
signed by Shri Raghunath Ghosh,
General Secretary Containers and
Closures Staff and Shramik Union
Gorifa 24—Parganas regarding en-
quiry into affairs of the Containers
and Closures Limited and its nationa-
lisation

12.41½ hrs

STATEMENT RE REOPENING OF
RAILWAY SPONSORED STUDENTS'
HOSTEL AT PATNA JUNCTION

रेल मंत्री (प्रो० मधु बबबते) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री राम बिलास पासवान न मई 1974 में पटना में रेलवे सहायता प्राप्त छात्रावास के बन्द किये जाने तथा इसे पुन न खोलने के सम्बन्ध में किये गये हाल के निणय का उल्लेख किया। मैंने कल सदन को आश्वासन दिया था कि एक दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया जायेगा। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि पटना में सहायता प्राप्त छात्रावास जा बन्द होने के 15 वर्ष पूर्व से बल रहा था को पुन खोलने का आज निर्णय कर लिया गया है। छात्रावास के सुचारुरूप में सञ्चालन की व्यवस्था करने के लिये पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि आश्वासन-पत्रों की मसुमिन छान-बीन की जायेगी ताकि केवल पात्र छात्रों को ही छात्रावास में भर्ती किया जाये।

SHRI N SREEKANTAN NAIR
(Quilon) On a point of order Gener

ally Ministers make statements in English because in this House we do not understand Hindi. If he wants, he can lay the Hindi version on the Table, that was the practice all along. May I request him to speak in English?

MR SPEAKER The Member had raised it in Hindi, you were not present when the Member spoke in Hindi that is why he is making a statement in Hindi. There is no point of order in this

12.43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(1) REPORTED PRESS RELEASE BY THE
RAILWAYS ABOUT HOLDING UP OF RAIL-
WAY WAGONS BY COAL INDIA LTD ETC

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : 27 मार्च का रेलवे ने एक प्रेस विज्ञापित जारी की है जा 28 मार्च का हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ग्रूप इन्डिया में छपी है। उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।

'The blame must surely rest on (Coal India Ltd, the collieries, the steel plants and some other thermal power plants who receive coal on priority but hold up the wagons'

रेलवे का यह कहना है इस प्रेस विज्ञापित के द्वारा कि 10 हजार बौंस प्रति दिन इन को देते हैं, जिन में से कोल इन्डिया लि० के खदानों से 900 बौंस प्रति दिन नहीं भर पाते हैं और इस तरह से 9 प्रतिशत शक्ति का नुकसान होता है और कोयला खदानों के मुह पर पडा रहता है। इस्पात के कारखानों में स्टील प्लान्ट्स में 2300 बौंस बौंस प्रति दिन नहीं भरे जाते हैं और वे यहा पर पडे रहते हैं और थर्मल पावर प्लान्ट 300 बौंस प्रति दिन भरने में असमर्थ रहते हैं। इस के कारण

[श्री निर्मल चन्द जैन]

बैंगन्स वही पर रूक जाते हैं और दूसरी जगह जहाँ उन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर नहीं भेजे जा सकते हैं। कोल इन्डिया ने यह कहा है और ऊर्जा मंत्री जी का भी एक बक्तव्य है कि अप्रैल 1977 से फरवरी 1978 तक 90.7 मिलियन टन कोल निकाला गया और रेलवे मंत्रालय की प्रैम विज्ञप्ति के द्वारा उन का यह कहना है कि 87 मिलियन टन कोयले के लिए 1978-79 में बे बैंगन देने में समर्थ हैं यानी जितना कोयला निकाला गया उस से कम कोयले के बैंगन दिये जाते हैं लेकिन फिर भी वे उस का लदान करने में असमर्थ हैं और कोयला वही पड़ा रहता है और बैंगन्स भी वहीं पड़े रहते हैं। यह सब को ज्ञात है कि देश में कोयले की बहुत कमी है। इस तरह से इन दोनों विभागों से जो बिसर्गति पैदा हुई है, उस को दूर करना चाहिए। यदि रेलवे मंत्रालय का कहना सही है, तो ऊर्जा मंत्री को इस और ध्यान देना चाहिए जिस से कोयला बहाना पड़ा रहे और कोयले का बहा से लदान हो सके और देश के अन्य भागों में वह जा सके। उन्हें रेलवे मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहिए कि आप हमें इतने बैंगन दीजिए जिन को भरने में हम समर्थ हैं। क्योंकि दोनों विभाग सरकार के पास हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के ये दोनों विभाग मसूदा कर के किसी प्रकार के नतीजे पर पहुँचे जिससे कि सभी को कोयला मिल सके।

(11) REPORTED AGITATION BY PADDY PRODUCERS FOR RAISING THE PRICE OF PADDY IN ANDHRA PRADESH

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) Sir, the Minister of Agriculture is not here If I make the statement

MR SPEAKER If you want you can make the statement

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will it be conveyed to him?

MR. SPEAKER It has already been conveyed to him

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU: In Andhra Pradesh, the paddy producers are agitating for raising the price of paddy

MR SPEAKER You know the rules Whatever you have given that should be read out Under rule 377, you cannot make a speech You must have seen the bulletin

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU. Yes, I have seen the bulletin Sir, that demand has not been accepted till now At the same time the paddy is not purchased The paddy is of two kinds— one is cyclone affected and the other is good paddy The cyclone affected paddy can be boiled and can be sent to Kerala and other places where they are taking it The other paddy can be purchased but the FCI is not purchasing Now the price is Rs 45 per 75 kg whereas the price fixed is Rs 75 In Circars district a large quantity is available and therefore it must be purchased Therefore, I request the hon Minister to see that all the paddy is purchased at the fixed price

(11) CONSTITUTIONS OF A BENCH OF HIGH COURT FOR MARATHWADA

श्री केशव राव बोंबले (नरदेड) अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 377 के द्वारा विधि और न्याय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठवाडा क्षेत्र के पांच जिलों के लिए अभी तक औरंगाबाद में हाई कोर्ट की बेंच का इन्तजाम नहीं किया गया है। वहाँ के लोग महाराष्ट्र सरकार से वहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच कायम करने की मांग करते रहे हैं। वहाँ की बार एसोसियेशन ने भी वहाँ हाई कोर्ट की बेंच कायम करने की मांग की है। मैं बीस साल असेम्बली में भी इस बारे में सवाल करता रहा हूँ। प्रशासकीय प्रस्ताव लाया गया। मुझे प्राप्तासन मिला।